

Shri S. C. Samanta:
Shri Subodh Hansda:
Shri D. C. Sharma:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri Yashpal Singh:
Shri Kolla Venkalah:
Shri M. N. Swamy:
Shri Laxmi Dass:
Shri Vasudevan Nair:
Shri Warior:
Shri Daji:
Shrimati Renuka Barkataki:
Shri Bagri:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri R. S. Pandey:
Shri Rajeshwar Patel:
Shri Ravindra Varma:
Shri Ram Harkh Yadav:
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether a loan agreement has recently been signed between India and U.S.A. for the purchase of U.S. fertilizers;

(b) if so, the terms of the agreement; and

(c) how much quantity of fertilizers will be purchased thereunder?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) and (b). The Agreement relating to the "Fertilizer Commodity Loan 1966" for \$50 million (Rs. 23.81 crores) was signed with the United States Agency for International Development on 4th January, 1966. The loan will be used to finance the foreign exchange costs of imports of fertilizer from the U.S.A. in categories approved by the U.S. A.I.D.

According to the agreement, there is to be no repayment of the principal amount for the first ten years; the repayments will then commence and be made in approximately equal half yearly instalments over the next thirty years. Interest is payable semi-annually in dollars at the rate of 1 per cent per annum during the first 10 years and thereafter at the rate of 2½% per annum for the remaining

30 years. Interest would accrue from the date of respective disbursements under the Loan and the first instalment is to be paid six months after the first disbursement or such earlier date as U.S. A.I.D. may specify.

(c) The Loan Agreement itself does not specify the quantity of each of the categories of fertilizers to be purchased under the Loan. However, orders have so far been placed by Government for import of 5,95,000 metric tons of ammonium sulphate and 1,50,500 metric tons of ammonium phosphate on U.S. suppliers under the Loan.

भोजन में पोष्टिक तत्वों की कमी

847. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री चिदम्बनाथ पाण्डेय :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान यूनैस्को के पोषण विशेषज्ञ डा० डी० के० फरिस के इस कथन की ओर गया है कि भारत में लगभग 20 प्रतिशत बालिग जनसंख्या को सन्तुलित भोजन नहीं मिलता है जिसके कारण वे कठिन शारीरिक कामकाज करने में असमर्थ हैं ;

(ख) यदि हां, तो भ्रूंसत भारतीयों को भोजन में प्रोटीन और विटामिनों की जो कमी होती है उसे दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ग) क्या इसका अनुमान लगाया गया है कि एक भ्रूंसत भारतीय को कब तक सन्तुलित भोजन दिया जा सकेगा ;

(घ) क्या इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) 15 और 16 फरवरी, 1964 को कलकत्ता में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय विकास सोसाईटी के एशियायी सेमिनारमें डा० फेरिस द्वारा पढ़े गये उस अभि-भाषण के बारे में सरकार को मालूम है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की कुल जनसंख्या का आधा भाग अथवा साढ़े बाईस करोड़ व्यक्ति जिनमें 15 करोड़, 15 साल से अधिक आयु के हैं 12 रुपये अथवा उससे कम मासिक पर अपना गुजारा कर रहे हैं। वे ऐसे खाद्य पर जीवित हैं जिससे घीसतन 50 प्रतिशत से अधिक कार्यकुशलता नहीं मिल सकती।

(ख) से (ङ). लोगों के पोषकीय स्तर को सुधारने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

1. यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा खाद्य एवं कृषि संघ के सहयोग से एक विस्तृत/व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ साथ सुरक्षित खाद्यों तथा प्रोटीन युक्त खाद्यों के उत्पादन तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने एवं चुने हुए सामुदायिक विकास कक्षों में जनसंख्या के सुभेदवर्गों में उन खाद्यों के वितरण की बात निहित है। यह कार्यक्रम, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, मैसूर, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। बिहार और दिल्ली में सरकार ने इस कार्यक्रम के प्लान आफ प्रारंशनों पर 1 फरवरी, 1966 को हस्ताक्षर कर लिए हैं। जम्मू व काश्मीर, गोवा, गुजरात, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए प्लान आफ प्रारंशन विचाराधीन है।

2. मूंगफली जैसे तिलहनों से मनुष्यों के खाने के लिए मूल्यवान बनस्पति प्रोटीन नष्ट होने से बचाने की दिशा में कदम उठाये

गये हैं। यह बनस्पति तेल-उद्योग का एक बाईबप्रोडक्ट हो गया है। यूनिसेफ की सहायता से बम्बई और कोयम्बतूर में खाने योग्य मूंगफली का घाटा तैयार करने के लिए प्रति वर्ष तीन तीन हजार टन की क्षमता के पाईलेट यूनिट खोले जा चुके हैं। ये यूनिट इस की व्यवहारिकता, स्टैंडर्ड टेक्निकों एवं उत्पादन अर्थशास्त्र का प्रदर्शन करेगे और 20 लाख टन से अधिक खाने योग्य मूंगफली के घाटे की संभावना बूढ़ निवालने के लिए एक बड़े कार्यक्रम के लिए उपभोग नमूना स्थापित करने में मदद देंगे।

3. केन्द्रीय खाद्य टेक्नालोजी अनुसन्धान संस्थान मैसूर में "बहुदेशीय खाद्य" तैयार किया है। इसमें 75 अंश मूंगफली के घाटे का है और 25 अंश बंगाल चने के हैं। साथ ही इस में उपयुक्त आवश्यक खनिज तथा विटामिन भी दिये गये हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता में सरकारी क्षेत्र में एक टन प्रति दिन की क्षमता का एक बहुदेशीय खाद्य एकक स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीतापुर और कोटद्वार में प्रतिदिन एक टन क्षमता के दो एकक गैर-सरकारी उद्योग के सहयोग से खोले हैं। दिल्ली और बम्बई के भी एक-एक ऐसे एकक खोलने का प्रबन्ध विचाराधीन है।

4. पीष्टिक घाटा जिसमें 5 से 10 प्रतिशत तक मूंगफली का घाटा तथा प्रोटीन, विटामिन, खनिज जैसे उपयुक्त पीष्टिक तत्व सम्मिलित होंगे, के उत्पादन के लिए एक गैर-सरकारी घाटा मिल के सहयोग से बम्बई में एकक खोला गया है। आशा है पीष्टिक घाटे का उत्पादन भीघ्र ही शुरू हो जायेगा। अन्य क्षेत्रों में ऐसे ही एकक खोलने का भी विचार किया जा रहा है।

5. राज्य सरकारों के माध्यम से गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं, स्कूल पूर्व तथा स्कूल जाने वाले बच्चों और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों

श्रीर अस्पतालों में रोगियों को स्किमड मिल्क मछली का तेल, बहु उद्देश्यीय खाद्य तथा विटामिन तथा आईरन टेबलेट्स जैसे सुरक्षित खाद्य दिये जा रहे हैं ।

6. प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को स्कूल में भोजन देने के विचार से 1962-63 से "केअर" तथा कैंथोलिक रिलीफ सर्विसेज के सहयोग से स्कूल भोजन का एक कार्यक्रम चलाया गया है । तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक एक करोड़ बच्चों को स्कूल आहार देने का विचार था ।

7. खाद्यान्नों के उपभोग में कमी करने के उद्देश्य से तथा इसके साथ साथ प्रधान अनाजों के बदले में बहुत से पीष्टिक, पूर्ण एवं विफायत-शार महत्वपूर्ण सहायक खाद्यान्नों का प्रयोग कर पोषण में सुधार लाने का एक कार्यक्रम खाद्य विभाग की तीसरी और चौथी योजनाओं में सम्मिलित किया गया है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक परियोजना का उद्देश्य सहायक खाद्यों को लोकप्रिय बनाने, उपयुक्त आहार सम्बन्धी धारतें बनाने, पीष्टिक एवं सन्तुलित आहार के बारे में सूचना देने और खाद्य संरक्षण को लोक प्रिय बाने का एक क्रमिक अभियान चलाना है । इस कार्य के लिए एक खाद्य एवं पोषण विस्तार सेवा जिस में एक सुप्रसाधित एवं पर्याप्त कर्मचारियों वाले सचल एकक हैं, शुरू की गई है । खाद्यान्नों की उपलब्धि को बढ़ाने तथा अच्छी विस्म के खाद्य उपलब्ध करने के कुछ तकनीकी साधनों का प्रयोग भी किया जा रहा है ।

8. खाद्य उपयोगिता एवं व्यवस्था के क्षेत्र में प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की व्यवस्था करने तथा आहार व्यपवर्तन के लिए नाभि विन्दुओं का कार्य करने के उद्देश्य से बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में कंटरिंग टेकनोलोजी और अप्लाईड न्यूट्रिशन के चार स्थान खोलने का एक कार्यक्रम खाद्य विभाग द्वारा तैयार किया गया है । फूड-

काफ्ट्स में प्रशिक्षण देने तथा आहार व्यपवर्तन के नाभि विन्दुओं के रूप में कार्य करने और खाद्य उपयोगिता और उसकी व्यवस्था के लिए देश के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर 20 फूड पोलिटेक्निक खोलने का भी यह विभाग विचार कर रहा है ।

9. अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद्, दी इंस्टीट्यूट आफ कटरिंग टेकनोलोजी एण्ड अप्लाईड न्यूट्रिशन, बम्बई, दी सेन्ट्रल फूड टेक्नालाजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर और न्यूट्रिशन रिसर्च लेबोरेटरीज, हैदराबाद द्वारा तैयार किये संतुलित आहार की सूचियों को लोक प्रिय बनाने के काम उठाये गये हैं ।

10. एक औसत भारतीय को सन्तुलित आहार प्रदान करने में कितना वक्त लगेगा इसका अभी तक कोई अनुमान नहीं किया गया है ।

11. डेरी विकास कार्यक्रम के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लगभग 19 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जिसमें से लगभग 15 करोड़ रुपये खर्च हो गये हैं इस कार्य के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में 36 करोड़ रुपये की और व्यवस्था की गयी है ।

Yamuna Barrage near Indraprastha Estate, New Delhi

848. Shri Heda: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) when the Yamuna barrage near the Indraprastha Estate, New Delhi will be completed; and

(b) the main purpose of the barrage?

The Minister of Irrigation and